नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 137
दि. 19.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एआई समिट में चीनी रोबोट विवाद से घिरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सरकार की सख्ती ने उठाए आत्मनिर्भरता और विश्वसनीयता पर सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की तकनीकी क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 उस समय विवादों के केंद्र में आ गया, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित किए गए रोबोट डॉग और ड्रोन की वास्तविकता पर सवाल खड़े हो गए। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य भारत की एआई क्षमता, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था, लेकिन इस घटना ने न केवल एक विश्वविद्यालय की साख पर प्रश्नचिह्न लगा दिया, बल्कि पूरे आयोजन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर भी बहस छेड़ दी।

समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक अत्याधुनिक रोबोट डॉग और ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसे लेकर विश्वविद्यालय ने दावा किया कि यह उनकी अपनी एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का परिणाम है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी कहा कि उन्होंने लगभग 350 करोड़ रुपये के निवेश से अपना एआई इकोसिस्टम तैयार किया है और इसी स्वदेशी तकनीकी ढांचे के तहत इन रोबोटिक उत्पादों को विकसित किया गया है। यह दावा भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का संदेश वैश्विक समुदाय तक पहुंचे।

हालांकि, यह दावा अधिक समय तक बिना विवाद के नहीं रह सका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तकनीकी विशेषज्ञों और

उपयोगकर्ताओं ने इन रोबोटिक उत्पादों की बनावट, डिजाइन और कार्यप्रणाली की तुलना चीन में पहले से उपलब्ध समान तकनीकों से करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह तकनीक चीन की कंपनियों द्वारा विकसित उत्पादों से मिलती-जुलती है और संभवतः वही तकनीक यहां प्रदर्शित की गई है। इन आरोपों के सामने आने के बाद यह मामला तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ।

विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी संस्थान को ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनका वास्तविक विकास उसने स्वयं नहीं किया हो। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती और यह सभी भाग लेने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे केवल उन्हीं उत्पादों को प्रदर्शित करें, जिनका निर्माण और विकास उन्होंने स्वयं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य देश की वास्तविक तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करना होता है, न कि किसी अन्य देश की तकनीक को अपने नाम से प्रस्तुत करना।

सरकार की इस सख्ती के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट संकेत गया कि सरकार इस तरह की घटनाओं को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। यह कदम न केवल इस विशेष मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे यह संदेश भी गया कि भारत अपनी तकनीकी पहचान और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की भ्रामक प्रस्तुति को स्वीकार नहीं करेगा।

इस विवाद ने भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास की दिशा में चल रहे प्रयासों पर भी व्यापक बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार और निजी संस्थान दोनों ही इस दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं और भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।

इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समिट देश की वास्तविक तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने के बजाय एक प्रचार का माध्यम बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आयोजन में अव्यवस्था और पारदर्शिता की कमी दिखाई दी और इससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि आयोजन में उचित निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया का अभाव था।

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद से भारत के तकनीकी संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सामने आया है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के इस दौर में केवल तकनीक का प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई संस्थान किसी अन्य देश की तकनीक को अपने नाम से प्रस्तुत करता है, तो इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, बल्कि पूरे देश की तकनीकी छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले संस्थानों के लिए सत्यापन और पारदर्शिता की प्रक्रिया को और मजबूत करना आवश्यक होगा। सरकार और आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शित किए जाने वाले सभी उत्पाद वास्तव में स्वदेशी विकास का परिणाम हों और उनके दावों की जांच पहले से ही कर ली जाए।

मध्य-पूर्व में युद्ध की आहट: समंदर से आसमान तक अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन, ईरान-रूस-चीन भी मैदान में

(जीएनएस)। वाशिंगटन। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां कूटनीति और सैन्य शक्ति आमने-सामने खड़ी हैं। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति को एक नई बेचैनी में डाल दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 50 से अधिक अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को मध्य-पूर्व की ओर भेजे जाने के फैसले ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि स्थिति केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब सैन्य तैयारियां खुलकर सामने आ चुकी हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में वार्ता का दूसरा दौर समाप्त हुआ है और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई पहले से अधिक गहरी होती दिखाई दे रही है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अंतरराष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने वाले संगठनों ने पुष्टि की है कि अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान लगातार मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। यह केवल संख्या का मामला नहीं है, बल्कि इन विमानों की क्षमता और उनकी रणनीतिक तैनाती का महत्व कहीं अधिक बड़ा है। ये विमान दुनिया के सबसे उन्नत और घातक युद्धक विमानों में गिने जाते हैं, जो किसी भी संभावित संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इस सैन्य तैनाती का उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से रणनीतिक दबाव बनाना भी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि

अमेरिका ने केवल हवाई शक्ति ही नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति को भी सक्रिय कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के दो विशाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें शामिल विमानवाहक पोत, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर और अन्य युद्धपोत किसी भी संभावित सैन्य संघर्ष में अमेरिका को अत्यधिक बढ़त प्रदान कर सकते हैं। यह तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। दूसरी ओर, ईरान ने भी इस सैन्य दबाव का जवाब अपनी सैन्य तैयारियों के माध्यम से देना शुरू कर दिया है। ईरान ने 'स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' नामक युद्धाभ्यास शुरू किया है, जो केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करना और मिसाइल परीक्षण करना यह दर्शाता है कि ईरान अपनी सामरिक शक्ति और नियंत्रण क्षमता को लेकर गंभीर है।

इस तनाव का प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अन्य वैश्विक शक्तियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं। रूस ने अपनी नौसेना टुकड़ी को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भेजा है, जो इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का संकेत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रूस समुद्रों में बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। यह बयान केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है कि रूस इस क्षेत्र में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार है।

इसी तरह, चीन ने भी हॉर्मुज क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चीन का यह कदम केवल एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। चीन लंबे समय से मध्य-पूर्व के ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर रहा है और इस क्षेत्र में उसकी सक्रियता इस बात का संकेत है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है।

मध्य-पूर्व में यह बढ़ती सैन्य गतिविधि केवल क्षेत्रीय संघर्ष का संकेत नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन के परिवर्तन का प्रतीक भी है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की सक्रियता यह दर्शाती है कि दुनिया एक नए भू-राजनीतिक युग में प्रवेश कर रही है, जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और नए गठबंधन बन रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कूटनीतिक दबाव का एक साधन भी है। अमेरिका द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ईरान को यह संदेश देने के लिए है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर गंभीर है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वहीं ईरान भी अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करके यह दिखाना चाहता है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है।

इस बढ़ते तनाव का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष या अवरोध वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात पर निर्भर हैं।

कांग्रेस में वैचारिक बहस तेज: मणिशंकर अय्यर बोले-मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हूं, राहुलवादी नहीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति में वैचारिक पहचान और नेतृत्व को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह बहस किसी बड़े दल के भीतर से उठती है, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में दिए अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं। उनका यह बयान न केवल कांग्रेस के अंदरूनी हालात की ओर संकेत करता है, बल्कि पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के बीच मौजूद वैचारिक दूरी को भी उजागर करता है।

अय्यर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस देश में विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनका वैचारिक आधार उन नेताओं से जुड़ा है, जिनके साथ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया या जिनके विचारों से वे गहराई से प्रभावित हुए। उनका कहना था कि राहुल गांधी उनसे लगभग 30 वर्ष छोटे हैं और उन्हें उनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वे स्वयं को राहुलवादी नहीं मानते।

अय्यर ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं को इंदिरावादी नहीं कहा, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बताया, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचाया। अय्यर के अनुसार, किसी भी लोकतांत्रिक

व्यवस्था में असहमति की आवाज को दबाना उचित नहीं होता और आपातकाल इसी सिद्धांत के विपरीत था।

अपने वैचारिक जुड़ाव को समझाते हुए अय्यर ने महात्मा गांधी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बचपन में जब महात्मा गांधी ने उन्हें गोद में उठाकर स्नेह दिया था, तब से उनके मन में गांधीवादी विचारधारा के प्रति गहरा सम्मान और लगाव पैदा हुआ। गांधीजी के सत्य, अहिंसा और नैतिकता के सिद्धांतों ने उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को गहराई से प्रभावित किया।

इसी तरह, अय्यर ने जवाहरलाल नेहरू के प्रति भी अपने वैचारिक सम्मान को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उनका बचपन और युवावस्था नेहरू के प्रधानमंत्री काल में बीती, जब देश आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ रहा था। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नीतियों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और यही कारण है कि वे स्वयं को नेहरूवादी मानते हैं।

अय्यर ने राजीव गांधी के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने का अवसर दिया, जिससे उन्हें प्रशासन और शासन की गहरी समझ विकसित करने का मौका मिला। राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसने भारत को एक नई दिशा दी।

अय्यर का यह बयान केवल व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर वैचारिक विविधता और आंतरिक लोकतंत्र के महत्व को भी रेखांकित करता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए असहमति को स्वीकार करना आवश्यक होता है। यदि पार्टी के भीतर असहमति की आवाज को दबाया जाता है, तो यह उस दल के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अय्यर का यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रही वैचारिक बहस का हिस्सा है। कांग्रेस एक ऐसा दल रहा है, जिसकी विचारधारा समय के साथ विकसित होती रही है और जिसमें विभिन्न नेताओं के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी, नेहरू और राजीव गांधी की विचारधाराओं ने कांग्रेस की पहचान को आकार दिया है, लेकिन वर्तमान समय में पार्टी नए नेतृत्व और नई चुनौतियों का सामना कर रही है।

अय्यर के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच वैचारिक स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति की भावना अभी भी मौजूद है। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती उसके भीतर मौजूद विविध विचारों और आंतरिक लोकतंत्र पर निर्भर करती है।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और विभिन्न दल अपनी-अपनी विचारधाराओं को लेकर स्पष्ट रुख अपना रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखे। मणिशंकर अय्यर का यह बयान कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दे सकता है और पार्टी के भविष्य की दिशा को लेकर नए सवाल खड़े कर सकता है।

भारत-ब्राजील की नई रणनीतिक दोस्ती: व्यापार, तकनीक और वैश्विक संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक कदम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य के बीच भारत और ब्राजील के रिश्ते एक नए और मजबूत दौर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का 18 से 22 फरवरी तक का भारत दौरा केवल एक औपचारिक राजकीय यात्रा नहीं है, बल्कि यह दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे लूला अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं, जिसमें 14 मंत्री, 260 से अधिक कंपनियों के मालिक, शीर्ष अधिकारी और प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ब्राजील भारत को केवल एक मित्र देश के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। लूला डी सिल्वा की यह छठी भारत यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत और भरोसेमंद संबंधों की निरंतरता को दर्शाती है। इससे पहले वे सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आए थे, जहां वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। इस बार उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक मंचों पर साझा रणनीति को मजबूत करना है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नए साझेदारों की तलाश में हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। ब्राजील द्वारा इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजना इस बात का प्रमाण है कि वह भारत के साथ अपने आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को व्यापक स्तर पर विस्तार देना चाहता है। ब्राजील के साथ आए CEO और उद्योगपति भारत में आयोजित व्यापार मंच में भाग लेंगे,

जहां दोनों देशों के बीच निवेश, उद्योग, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यह मंच न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच प्रत्यक्ष संपर्क और साझेदारी के नए अवसर भी प्रदान करेगा। भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनते जा रहे हैं। ब्राजील के व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रमुख जॉर्ज वियाना के अनुसार, भारत अब ब्राजील का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो दोनों देशों के बढ़ते आर्थिक संबंधों का स्पष्ट संकेत है।

इस यात्रा के दौरान मर्कसुर और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है। मर्कसुर दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक समूह है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। यदि यह समझौता सफल होता है, तो इससे भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। यह समझौता भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों को दक्षिण अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

तकनीकी और औद्योगिक सहयोग भी इस यात्रा का एक प्रमुख पहलू है। ब्राजील की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर SA के भारतीय बाजार में प्रवेश की घोषणा की संभावना है, जो भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। इससे भारत में विमान निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और रक्षा उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। ब्राजील की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बड़ी मात्रा में दवाओं की आवश्यकता होती है और भारत, जो दुनिया का प्रमुख फार्मास्युटिकल उत्पादक देश है, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इस सहयोग से न केवल ब्राजील को सस्ती और प्रभावी दवाएं मिलेंगी, बल्कि भारत के फार्मा उद्योग को भी एक बड़ा बाजार प्राप्त होगा।

पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्राजील द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 वर्ष की बहु-प्रवेश वीजा प्रणाली की घोषणा की संभावना भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ेगा और सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक महत्व भी है। भारत और ब्राजील दोनों ही BRICS और G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों के सदस्य हैं और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी साझा सोच और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों देश विकासशील देशों के हितों की रक्षा और वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

ब्राजील का यह कदम इस बात का संकेत भी है कि वह अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ब्राजील के लिए एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में उभर रहा है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करेगी और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग को मजबूत बनाएगी। यह दौरा न केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास, मित्रता और साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत भी करेगा।लूला डी सिल्वा की भारत यात्रा इस बात का प्रतीक है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और ब्राजील जैसे देश अपनी साझेदारी के माध्यम से एक संतुलित, सहयोगात्मक और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह यात्रा भविष्य में दोनों देशों के बीच मजबूत, स्थायी और बहुआयामी संबंधों की नींव को और अधिक मजबूत करेगी और वैश्विक मंच पर उनकी संयुक्त शक्ति और प्रभाव को बढ़ाएगी।

संपादकीय

फसल बीमा का पूरा लाभ मिले किसान को

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को वर्ष 2016 में बड़े उत्साह और उम्मीदों के साथ शुरू किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित मौसम और कृषि से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना था। भारत में खेती सदियों से प्रकृति पर निर्भर रही है, और किसान हर वर्ष सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात और असमय वर्षा जैसी आपदाओं का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसान की पूरी साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाती है, जिससे वह आर्थिक संकट, कर्ज और मानसिक तनाव के दलदल में फंस जाता है। इस गंभीर समस्या का समाधान करने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट था कि यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाती है, तो उसे बीमा के माध्यम से उचित मुआवजा दिया जाएगा, ताकि वह दोबारा खेती करने के लिए सक्षम रह सके। योजना में किसानों के लिए प्रीमियम दरें बहुत कम रखी गईं, जबकि शेष प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया गया। इसका मतलब यह था कि सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि किसानों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुरक्षा मिले।

लेकिन दस वर्षों के अनुभव के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह योजना वास्तव में अपने उद्देश्य में सफल रही है। उपलब्ध आंकड़े और जमीनी सच्चाई यह संकेत देती है कि योजना का लाभ किसानों तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। कई मामलों में बीमा कंपनियों को भारी लाभ हुआ है, जबकि किसानों को उनके नुकसान की तुलना में बहुत कम मुआवजा मिला है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में वर्ष 2023 से 2025 के बीच बीमा कंपनियों ने 2,827 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, लेकिन किसानों को केवल 731 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसका अर्थ यह है कि बीमा कंपनियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ, जो योजना की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी प्रकार राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में भी अनियमितताओं और असंतुलन की शिकायतें सामने आई हैं। देशभर के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में बीमा कंपनियों ने 82,015 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, जबकि किसानों को केवल 34,799 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों को लगभग 47,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। यह स्थिति योजना की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि योजना का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा देना था, न कि बीमा कंपनियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाना। इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी दावों के निपटान में देरी और पारदर्शिता की कमी रही है। कई किसानों को उनके दावे के भुगतान के लिए महीनों या वर्षों तक इंतजार करना पड़ा है। जब तक उन्हें मुआवजा मिलता है, तब तक वे पहले ही कर्ज में डूब चुके होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। कई मामलों में किसानों के दावे बिना उचित कारण के खारिज कर दिए गए, जिससे किसानों में निराशा और अविश्वास की भावना पैदा हुई है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के मामले भी सामने आए हैं। जाली दस्तावेजों, फर्जी बैंक खातों और गलत जानकारी के माध्यम से योजना का दुरुपयोग किया गया है। इससे न केवल सरकारी धन की हानि हुई है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद किसान भी इससे वंचित रह गए हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि योजना के क्रियान्वयन में निगरानी और नियंत्रण की कमी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस योजना में प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जो करदाताओं के पैसे से आता है। जब सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है, तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। यदि बीमा कंपनियां इस योजना से अत्यधिक लाभ कमा रही हैं, जबकि किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग पर भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि सरकार ने योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई तकनीकी सुधारों को लागू करने का प्रयास किया है। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन तकनीक और डिजिटल डेटा का उपयोग करके फसल नुकसान का सटीक आकलन करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य दावों के निपटान को तेज और पारदर्शी बनाना है। लेकिन इन उपायों का प्रभाव अभी तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया है, और जमीनी स्तर पर किसानों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा कंपनियां योजना का दुरुपयोग न करें। इसके अलावा, दावों के निपटान की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके।

लिव-इन में दहेज कानून से संरक्षण की आस

> लिव-इन जैसे संबंधों में भी दहेज और आर्थिक दबाव जैसे आरोप सवाल उठाते हैं। क्या संकट दहेज प्रथा में है, या हमारी सामाजिक मानसिकता में? जो आधुनिक संबंधों में भी स्वार्थ और वर्चस्व के तत्वों को पुनः स्थापित कर देती है? कहीं दहेज या क्रूरता के आरोप टूटते लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से साधने, दबाव बनाने या प्रतिशोध लेने का माध्यम तो नहीं बन रहे?

हाल ही में देश को शीर्ष अदालत ने 'लोकेश बी.एच. एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले के आपराधिक कानून से जुड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए सहमति दी है। क्या किसी महिला के साथ विवाह जैसे संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में रहने वाले पुरुष को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए अभियोजन के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 18 नवंबर 2025 के निर्णय को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धारा 498ए उन मामलों में भी लागू हो सकती है जहां संबंध विवाह के समान प्रकृति का हो। गौरतलब है कि धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है, तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज से जुड़े उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करते हुए उसे नोटिस जारी किया है और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले से संबंधित समस्त डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही, इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रोक लगा दी गई है।

यह प्रश्न सरल या एकरेखीय नहीं है। इसके एक पक्ष में स्त्री के अधिकार, गरिमा और सुरक्षा का संवेदनशील प्रश्न निहित है, तो दूसरे पक्ष में विधि की वह मर्यादा भी है जिसके अंतर्गत दहेज-निरोधक तथा क्रूरता संबंधी प्रावधानों को पारंपरिक रूप से वैध वैवाहिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। एक ओर लिव-इन संबंध भारतीय समाज में गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं; वहीं दूसरी ओर, इनके साथ वे सभी जटिलताएं और विवाद भी सामने आ खड़े हो रहे हैं, जो प्रायः विधिसम्मत वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कानून मूलतः वैवाहिक संस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उन्हीं प्रावधानों का आश्रय लेते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े कानून के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस प्रकार, यह विमर्श केवल दंडात्मक कानून की तकनीकी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विधिक सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती भी है। सबसे अधिक विस्मयकारी पहलू यह है कि अनेक युवा तथाकथित आधुनिक जीवन-दृष्टि और स्वतंत्रता के आग्रह के साथ लिव-इन संबंधों में प्रवेश करते हैं, मानो वे सामाजिक तथा विधि-सम्मत परंपरागत व्यवस्थाओं को महत्व नहीं देते। परंतु विडंबना यह है कि जब विवाद या संकट उत्पन्न होता है, तो वही पक्ष उन कानूनी संरक्षणों की शरण में जाते दिखाई देते हैं, जो मूलतः पारंपरिक वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए थे। यह विरोधाभास एक ओर सामाजिक मान्यताओं से विमुखता और दूसरी ओर उन्हीं से उपजे विधिक संरक्षण की अपेक्षा—कानून के समक्ष निरंतर एक नया संतुलन स्थापित करने की चुनौती उपस्थित कर रहा है। जनवरी, 2004 को 'रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम एवं अन्य के मामले' में देश की शीर्ष अदालत ने कहा 'धारा 498ए को लागू करने के लिए 'पति' शब्द के अंतर्गत कौन-कौन आएगा, यह प्रश्न वास्तव में जटिल है। शब्दार्थ की दृष्टि से, विभिन्न विधि शब्दकोशों और शब्दावली में 'पति' तथा 'विवाह' की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनसे यह प्रतीत हो सकता है कि दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए वैध विवाह का अस्तित्व अनिवार्य शर्त है।' अदालत ने यह भी कहा कि 'दहेज' की अवधारणा मूलतः विवाह से जुड़ी होती है और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान भी विवाह के संदर्भ में ही लागू होते हैं। यदि स्वयं विवाह की वैधता ही विवादित हो, तो इससे अतिरिक्त विधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

अजयनाथ बनाम केरल राज्य, में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए अभियुक्त और पीड़िता के बीच वैध वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि कथित विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो, तो धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन कायम नहीं रह सकता। वर्ष 2003 के कलियापेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498ए अथवा उससे संबंधित प्रावधान स्वतः लागू नहीं हो जाते; इनके लिए विधि द्वारा मान्य वैवाहिक संबंध का अस्तित्व आवश्यक है। यदि विवाह ही वैध न हो या दहेज से जुड़ा तत्व स्थापित न हो, तो आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने विवाह को इन प्रावधानों के लागू होने की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। इसी तर्क का विस्तार तथाकथित 'पति के संबंधियों' तक भी होता है। जब विधिक दृष्टि से 'पति' का दर्जा ही सिद्ध न हो, तो उसके संबंधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी स्वतः कमजोर पड़ जाती है। यही नहीं जुलाई, 2024 में केरल उच्च न्यायालय ने 'डॉ. अश्विन वी. नायर बनाम केरल राज्य एवं अन्य' में यह निर्णय दिया कि किसी महिला का लिव-इन पार्टनर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत 'पति' की परिभाषा में नहीं आता। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पति शब्द का अर्थ है विवाहित पुरुष, जो विवाह में महिला का साथी हो। अतः विवाह ही वह तत्व है जो महिला के साथी को 'पति' का दर्जा देता है। विवाह का अर्थ है कानून की दृष्टि में वैध विवाह। इसलिए, बिना वैध विवाह के यदि कोई पुरुष किसी महिला का साथी बनता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के उद्देश्य से 'पति' की परिभाषा में नहीं आएगा।'

लिव-इन संबंधों की अवधारणा स्वयं इस दावे के साथ सामने आई कि यह पारंपरिक वैवाहिक बंधनों और उनसे जुड़ी सामाजिक बुराइयों विशेषतः दहेज जैसी कुरीतियों से मुक्त एक आधुनिक और स्वैच्छिक संबंध है। दहेज को लंबे समय से एक ऐसी परंपरागत सामाजिक बुराई के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसने स्त्रियों के अधिकारों का शोषण किया और वैवाहिक संस्था को कलंकित किया। यदि लिव-इन संबंध स्वतंत्रता, समानता और आधुनिक चेतना के प्रतीक माने जाते हैं, तो फिर वहां दहेज जैसा प्रश्न उत्पन्न ही कैसे होता है?

यदि वास्तव में ऐसे संबंधों में भी दहेज या आर्थिक दबाव जैसे आरोप सामने आ रहे हैं तो यह गंभीर आत्ममंथन की मांग करता है। क्या समस्या केवल दहेज नामक प्रथा में है, या हमारी सामाजिक मानसिकता में, जो आधुनिक संबंधों में भी परंपरागत स्वार्थ और वर्चस्व के तत्वों को पुनः स्थापित कर देती है? या फिर यह भी विचारणीय है कि कहीं दहेज अथवा क्रूरता के आरोप कभी-कभी टूटते हुए लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से साधने, दबाव बनाने या प्रतिशोध लेने का माध्यम तो नहीं बन रहे? यह प्रश्न केवल विधिक व्याख्या का नहीं, बल्कि सामाजिक ईमानदारी और आधुनिकता की वास्तविक परिभाषा का भी है।

प्रेरणा

सत्य की खोज में समर्पित जीवनः गणित के संन्यासी हरीश चंद्र

ज्ञान और विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं, जिन्होंने केवल अपने शोध से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों की गहराई और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा से पूरी दुनिया को नई दिशा दी। हरीश चंद्र ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे, जिनका जीवन गणित की साधना का एक अद्वितीय उदाहरण है। वे केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साधक थे, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण ज्ञान की पूर्णता और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक संघर्ष और समर्पण की कहानी है, जो किसी को महान बनाता है।

यह प्रसंग उस समय का है जब हरीश चंद्र इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे। वहां उन्हें विश्व के महानतम भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के साथ काम करने का अवसर मिला। डिराक उस समय क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कार्य ने भौतिकी की समझ को पूरी तरह बदल दिया था। हरीश चंद्र उनके विद्यार्थी थे और उनसे बहुत कुछ सीख रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी। वे केवल यह नहीं जानना चाहते थे कि कोई सिद्धांत काम करता है या नहीं, बल्कि वे यह भी जानना चाहते थे कि वह सिद्धांत तार्किक और गणितीय रूप से पूरी तरह सही है या नहीं। एक दिन हरीश चंद्र ने देखा कि डिराक एक भौतिक समस्या को हल करते समय कुछ ऐसे गणितीय तर्कों का उपयोग कर रहे थे, जो पूरी तरह कठोर और प्रमाणित नहीं थे। यह देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने साहस करके अपने गुरु से पूछा, "क्या यह समीकरण गणितीय दृष्टि से हर स्थिति में पूरी तरह सही है?" यह प्रश्न उनके स्वभाव को दर्शाता है। वे किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वह प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कही गई थी। वे हर बात को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझना चाहते थे।

डिराक ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दिया। उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह गणितीय रूप से पूरी तरह सिद्ध है या नहीं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रकृति के अनुरूप काम करता है और उसके व्यवहार को सही ढंग से समझाता है।" यह उत्तर भौतिकी के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित था, क्योंकि भौतिकी का उद्देश्य प्रकृति के व्यवहार को समझना है। लेकिन हरीश चंद्र का मन इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उनके भीतर का गणितज्ञ पूर्ण सत्य चाहता था, ऐसा सत्य जो केवल अनुभव या अनुमान पर आधारित न हो, बल्कि जिसे पूरी तरह सिद्ध किया जा सके।

यह वही क्षण था, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन गणित की ओर अधिक आकर्षित है, क्योंकि गणित में हर बात को प्रमाणित किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की अनिश्चितता के लिए स्थान नहीं होता। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन गणित को समर्पित करेंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भौतिकी एक अत्यंत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक विश्वास का अनुसरण किया और गणित को अपना मार्ग बनाया।

इसके बाद हरीश चंद्र ने गणित के क्षेत्र में जो कार्य किया, वह अद्वितीय और ऐतिहासिक था। उन्होंने 'प्रेजेंटेशन थ्योरी' और 'हार्मोनिक एनालिसिस' के क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत विकसित किए, जिन्होंने गणित की समझ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि गणित केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की गहराई को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनके शोध ने न केवल गणित को समृद्ध किया, बल्कि भौतिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों को भी नई दिशा प्रदान की।

हरीश चंद्र का जीवन अत्यंत सरल और अनुशासित था। वे अपने काम में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता था। कई बार वे आधी रात को भी उठकर ब्लैकबोर्ड पर समीकरण लिखने लगते थे, क्योंकि उनके मन में कोई नया विचार आया होता था। उनके लिए गणित केवल एक पेशा नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी। वे ज्ञान की खोज में पूरी तरह समर्पित थे और उनके लिए यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था।

उनकी साधना और समर्पण ने उन्हें विश्व के महानतम गणितज्ञों की श्रेणी में ला खड़ा किया। उनके कार्य को पूरी दुनिया में सम्मान मिला और उन्हें गणित के क्षेत्र में एक अग्रणी विद्वान के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता थी। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद वे हमेशा सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति बने रहे। वे कभी प्रसिद्धि या सम्मान के पीछे नहीं भागे। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह संतोष था, जो उन्हें किसी जटिल समस्या का समाधान खोजने के बाद मिलता था।

भारत के लिए हरीश चंद्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय प्रतिभा विश्व स्तर पर किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपने कार्य से न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने। उनका जीवन यह सिखाता है कि महानता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि समर्पण, अनुशासन और सत्य की खोज के प्रति अटूट निष्ठा से प्राप्त होती है।

आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक सच्चे संन्यासी थे, जिन्होंने सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर ज्ञान की साधना को अपना जीवन बना लिया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए और कभी भी सत्य की खोज से पीछे नहीं हटना चाहिए।

भारत के लिए बड़ा सबक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद

20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 के लगभग वैश्विक एआई अग्रणी भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी तरह के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहा भारत, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर दावा भी किया है कि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी, प्रख्यात शोधकर्ता, बहुपक्षीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक एक साथ आएंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे।राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज़्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जाहिर सी बात है कि इस समिट के जरिए जहां चर्चा भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता और टैलेंट की होनी चाहिए थी, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली एआई समिट में पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एक प्रोफेसर ने बड़े ही गर्व के साथ चार पैरों वाले इस रोबोडॉग की खासियत भी कैमरे पर बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस प्रतिनिधि के हाव-भाव देखने लायक है।इसका नाम 'ओरियन' बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है। सरकारी चैनल सहित देश के कई मीडिया संस्थानों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोर-शोर से चलाया और छापा भी। लेकिन चीन की तरफ से बयान आते ही पूरा मामला पलट गया। इसके बाद यह पता लगा कि वास्तव में यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया गया एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि यह रोबोडॉग उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए यह भी कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे बनाने का दावा नहीं किया। जबकि उनके प्रोफेसर का वायरल वीडियो ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है।

ऐसे में एक बार फिर से सरकार के विजन, नीति और फंड की व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार प्राइवेट विश्विद्यालय और कॉलेजों के सहारे देश में नई, बड़ी और स्पेशल रिसर्च नहीं करवा सकती क्योंकि इनकी भूमिका और इनके कामकाज का पूरा ढांचा ही संदिग्ध है। एडमिशन से लेकर क्लास और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी कई बार गहरे सवाल खड़े हो चुके हैं। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट फाइल करने के नाम पर निजी विभविद्यालयों को जो मोटा फंड देती है, उसकी न्यायिक जांच करवाने का भी समय आ गया है।

दरअसल, यह बिल्कुल सही समय आ गया है कि सरकार पहले की तरह सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्विद्यालयों में शिक्षा हासिल कर रही प्रतिभाओं को हर तरह से उभारने में मदद करें। इन संस्थानों में फीस और लालफीताशाही दोनों कम होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और करप्शन पर हर हाल में लगाम होनी चाहिए।

अभियान

हिमालय की मौन ऊर्जा और मानव चेतना का ब्रह्मांडीय पुनर्जागरण

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण और अवसर होते हैं, जो केवल समय के प्रवाह का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे चेतना के द्वार खोलने वाले बिंदु बन जाते हैं। महाशिवरात्रि ऐसी ही एक रात्रि है, जिसे विशेष रूप से हिमालयी परंपराओं में चेतना के उत्कर्ष और आंतरिक पुनर्संयोजन की रात्रि के रूप में संरक्षित किया गया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव प्रणाली के बीच गहरे संबंधों की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। हजारों वर्षों से हिमालय की गुफाओं और एकांत स्थानों में साधकों ने इस रात्रि का उपयोग अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को समझने के लिए किया है। उन्होंने अनुभव किया कि इस विशेष रात्रि में प्रकृति स्वयं मानव चेतना को उसके मूल स्वरूप के निकट ले जाने में सहयोग करती है।

मानव शरीर केवल एक जैविक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील प्रणाली है, जो ब्रह्मांडीय लयों से निरंतर प्रभावित होती रहती है। पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का चक्र, सूर्य की स्थिति और ग्रहों की गति—ये सभी कारक मानव शरीर और मन पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। महाशिवरात्रि अमावस्या से ठीक पहले की वह अवस्था है, जब चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव मानव प्रणाली में ऊर्जा के प्रवाह को भीतर की ओर मोड़ देता है। इस समय बाहरी गतिविधियों का प्रभाव कम हो जाता है और चेतना स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होने लगती है। यह अंतर्मुखता किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य का परिणाम होती है।

हिमालयी साधकों ने अपने अनुभवों से यह जाना कि इस रात्रि में जागरूकता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः रात्रि का समय विश्राम और नींद के लिए होता है, लेकिन महाशिवरात्रि में जागरण का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह शरीर और चेतना को एक विशेष अवस्था में बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस रात्रि में जागता है और सजग रहता है, तब उसकी तंत्रिका प्रणाली अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हो जाती है। यह ग्रहणशीलता व्यक्ति को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करने की क्षमता प्रदान करती है।

मानव शरीर की संरचना में मेरुदंड का विशेष महत्व है। मेरुदंड केवल शरीर को सहारा देने वाली संरचना नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य मार्ग भी है। जब व्यक्ति सीधा बैठता है या खड़ा रहता है, तब मेरुदंड में स्थित तंत्रिका मार्ग संतुलित और सक्रिय हो जाते हैं। हिमालयी परंपराओं में यह माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि व्यक्ति अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखता है, तो उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्व दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह व्यक्ति को गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव कराता है।

इस रात्रि का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और भावनाओं के स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानव मन निरंतर विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से भरा रहता है। यह मानसिक गतिविधि व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में प्रकृति की ऊर्जा मानसिक गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से शांत करने में सहायता करती है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की मौन चेतना को अनुभव कर सकता है।

हिमालयी दर्शन में शिव को चेतना की उस अवस्था का प्रतीक माना जाता है, जहां पूर्ण स्थिरता और जागरूकता एक साथ उपस्थित होती है। शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वह अस्तित्व की वह अवस्था है, जहां कोई अशांति नहीं होती, कोई भ्रम नहीं होता, केवल स्पष्टता और संतुलन होता है। महाशिवरात्रि को शिव की रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चेतना की उसी स्थिर अवस्था को अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है।

ध्वनि और कंपन का भी इस रात्रि में विशेष महत्व होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग एक निश्चित कंपन में कार्य करता है। मानव शरीर और मस्तिष्क भी इन कंपन से प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है, तब वह एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करता है, जो उसकी तंत्रिका प्रणाली और मानसिक अवस्था को संतुलित करता है। हिमालयी साधकों ने यह अनुभव किया कि महाशिवरात्रि की रात्रि में मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय मानव प्रणाली अधिक ग्रहणशील होती है।

श्वास भी चेतना के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सामान्यतः श्वास एक स्वचालित प्रक्रिया होती है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी श्वास के प्रति जागरूक हो जाता है, तब वह अपनी चेतना को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में सजग श्वास व्यक्ति को उसके भीतर की गहराई तक ले जा सकती है। यह श्वास और चेतना के बीच के संबंध को स्पष्ट करती है और व्यक्ति को आंतरिक संतुलन प्रदान करती है।

आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि ध्यान, श्वास और जागरूकता का अभ्यास मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह तनाव को कम करता है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। हिमालयी साधकों ने इन प्रभावों को हजारों वर्षों पहले ही अपने अनुभवों के माध्यम से समझ लिया था।

महाशिवरात्रि का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक चेतना पर भी प्रभाव डालती है। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा न केवल व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करती है, बल्कि यह पूरे वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों लोग एक साथ जागरण और साधना करते हैं।

यह रात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को समझना और विकसित करना भी है। आधुनिक समाज में व्यक्ति बाहरी सफलता की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को भूल गया है। महाशिवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि सच्चा संतुलन और संतोष भीतर से उत्पन्न होता है।

हिमालय की परंपराएं हमें यह बताती हैं कि जब व्यक्ति प्रकृति की लयों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तब उसका जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित और शांत हो जाता है। महाशिवरात्रि इसी सामंजस्य का प्रतीक है। यह वह अवसर है जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को अनुभव कर सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।

महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह चेतना के विज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि मानव केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी चेतना है, जो ब्रह्मांड के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सुनियोजित टाउन प्लानिंग से बदली सूरत की तस्वीर, पांच वर्षों में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला 4,400 करोड़ से अधिक का राजस्व

(जीएनएस)। देश के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल सूरत ने पिछले पांच वर्षों में शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग कमेटी द्वारा तैयार की गई योजनाओं ने न केवल शहर के वर्तमान विकास को गति दी है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और व्यवस्थित शहरी ढांचे की नींव भी रखी है। इस सुनियोजित विकास का परिणाम यह रहा कि नगर निगम को इस अवधि में 4,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो शहर की आर्थिक और संरचनात्मक मजबूती का स्पष्ट संकेत है।

सूरत की पहचान आज केवल एक औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में भी स्थापित हो रही है। इसके पीछे नगर निगम की दूरदर्शी टाउन प्लानिंग नीति और व्यवस्थित भूमि प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए टाउन प्लानिंग विभाग ने पिछले पांच वर्षों में कुल 430 ड्राफ्ट टाउन प्लान तैयार किए, जिनका उद्देश्य शहरी विस्तार को नियंत्रित करना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया।

पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10.27 लाख वर्गमीटर भूमि के 46 प्लॉट अधिग्रहित किए गए। यह कदम शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया, ताकि नागरिकों को निर्बाध जल आपूर्ति और प्रभावी सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा, शहर के पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 12 हेक्टेयर क्षेत्र में डुमस सी फेस परियोजना विकसित की जा रही है। यह परियोजना न केवल सूरत के सौंदर्य को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

शहर के पूर्वी क्षेत्र में आभवा-उभराट रोड के विकास के लिए 90 लाख वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह परियोजना शहर के विस्तार और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही 362 आवश्यक सड़कों के निर्माण के लिए 30 लाख वर्गमीटर जमीन अधिग्रहित की गई, जिससे शहर के रोड नेटवर्क को मजबूती मिली है। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

सूरत में तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) परियोजना को भी प्राथमिकता दी गई है। यह परियोजना शहर के विभिन्न परिवहन माध्यमों को एकीकृत करने का कार्य करेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना 18,800 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही है और नगर निगम ने इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी है। इसके अतिरिक्त 20,000 वर्गमीटर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिससे यह परियोजना जल्द ही पूर्णता की ओर बढ़ सकेगी। मेट्रो परियोजना को भी सूरत के शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। नगर निगम द्वारा 1.81 लाख वर्गमीटर की 22 भूमि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित की गई है। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे गेटको और जीएमआरसी को कुल 2.22 लाख वर्गमीटर की 31 जमीनें आवंटित की गईं, जिससे नगर निगम को लगभग 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह राजस्व शहर के अन्य विकास कार्यों में निवेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

सूरत के शहरी विकास में बिल्डिंग परमिट और भवन स्वीकृति प्रक्रिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले पांच वर्षों में नगर निगम द्वारा 30,409 विकास परमिट, 9,192 प्लॉट सत्यापन प्रमाणपत्र और 1,478 भवन उपयोग प्रमाणपत्र जारी किए गए। इसके माध्यम से 4,068 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया एफएसआई प्राप्त हुआ, जो नगर निगम के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहा है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि शहर में निर्माण और विकास गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

नगर निगम द्वारा अपनाई गई एडवांस प्लानिंग नीति ने सूरत को अव्यवस्थित विकास से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजनाबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण, सड़क नेटवर्क की तैयारी और प्लॉट निर्माण की प्रक्रिया को लागू करने से शहर का विकास संतुलित और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। इससे न केवल नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है।

सूरत का विकास मॉडल अन्य शहरों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभर रहा है। सुनियोजित टाउन प्लानिंग, प्रभावी भूमि प्रबंधन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के माध्यम से सूरत ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि विकास योजनाओं को दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए, तो किसी भी शहर को आधुनिक और स्मार्ट शहर में परिवर्तित किया जा सकता है।

आज सूरत न केवल अपने औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सुव्यवस्थित शहरी संरचना और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी पहचान बना रहा है। नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों ने शहर को एक नई दिशा दी है, जिससे सूरत का भविष्य और भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के पूर्ण होने के साथ सूरत न केवल भारत के अग्रणी शहरों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

गुजरात बजट से सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊर्जा उद्योग और निर्यात को मिलेगा वैश्विक विस्तार का अवसर

(जीएनएस)। देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सूरत के लिए इस वर्ष का गुजरात बजट नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत करते हुए इसे उद्योग, निर्यात और विशेष रूप से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया है। चैंबर के अनुसार बजट में घोषित योजनाएं न केवल टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती देंगी, बल्कि सूरत को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सूरत लंबे समय से देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। यहां फाइबर उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग और तैयार परिधान तक की पूरी वैल्यू चेन मौजूद है। लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से जुड़ी हुई है और देश के कुल टेक्सटाइल उत्पादन और निर्यात में सूरत का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाइल स्कीम के तहत इस वर्ष 2,775 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना इस उद्योग के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। पिछले वर्ष यह आवंटन 2,000 करोड़ रुपये था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए इसके विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि टेक्सटाइल स्कीम के तहत घोषित प्रावधानों से सूरत के उद्योगों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधान उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करेंगे। इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्यात के अवसरों में वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादन से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकेगी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गठन की घोषणा भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह काउंसिल निर्यातकों को प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी, नीति समर्थन और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करेगी। इससे सूरत के उद्योगों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी और निर्यात प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित हो सकेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन मिलेगा।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान गुजरात को देश के अग्रणी औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में और मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निर्यात समर्थन और उद्योगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से राज्य की औद्योगिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ सूरत को मिलेगा, जहां पहले से ही मजबूत औद्योगिक आधार मौजूद है।

राज्य सरकार द्वारा छह आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह निवेश दक्षिण गुजरात में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योगों को संचालन में सुविधा मिलेगी और नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद और सूरत सहित चार क्षेत्रीय केंद्रों में आई-हब विकसित करने के लिए 80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह पहल टेक्नोलॉजी और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और युवा उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करेगी। टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के विकास से सूरत की औद्योगिक संरचना और अधिक आधुनिक और विविधतापूर्ण बनेगी। कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद और सूरत को सैटेलाइट टाउन से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की घोषणा भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर कनेक्टिविटी से माल और लोगों की आवाजाही तेज और सुविधाजनक होगी, जिससे व्यापार और उद्योग को लाभ मिलेगा। इससे शहरी विस्तार को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 25 जीआईडीसी को स्मार्ट जीआईडीसी के रूप में विकसित करने और 1,300 करोड़ रुपये से 120 मिनी जीआईडीसी के अपग्रेडेशन की योजना उद्योगों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और निवेश का माहौल मजबूत होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सूरत में अहमदाबाद के समकक्ष एक मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा से दक्षिण गुजरात के लोगों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी शहर के समग्र विकास के लिए आवश्यक होती हैं और इससे सूरत की सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बदल रहा भारत का बिजली और परिवहन तंत्र, शिकायत निस्तारण से लेकर ग्रिड प्रबंधन तक नई क्रांति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)। देश के ऊर्जा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई तकनीक का समावेश अब केवल प्रयोगात्मक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तब देखने को मिला, जब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान विद्युत मंत्रालय के विशेष प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी ने स्पष्ट संकेत दिया कि भारत का विद्युत तंत्र अब मेगावाट की पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर मेगाबाइट की डिजिटल क्षमता को अपनाते हुए एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।

इस अवसर पर प्रस्तुत की गई थीम 'मेगावाट से मेगाबाइट तकः भारत के विद्युत इको-सिस्टम का रूपांतरण' केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश के ऊर्जा तंत्र में हो रहे गहरे बदलाव का प्रतीक है। अब बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की जटिल प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। यह तकनीक न केवल बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बना रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पहले जहां उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित समस्याओं जैसे कटौती, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव या बिलिंग त्रुटियों के समाधान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब एआई आधारित सिस्टम इन शिकायतों का विश्लेषण कर तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचा देता है। यह सिस्टम शिकायत के प्रकार, स्थान और गंभीरता का स्वतः आकलन करता है और प्राथमिकता के आधार पर समाधान की प्रक्रिया शुरू करता है। इससे न केवल समाधान की गति बढ़ी है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत हुआ है। विद्युत मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म अब विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं। इससे बिजली उत्पादन कंपनियों को पहले से ही पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, जिससे उत्पादन और वितरण की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है। यह प्रणाली बिजली कटौती की संभावना को कम करने और ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।

इस डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रिड प्रबंधन में एआई का उपयोग है। बिजली ग्रिड एक अत्यंत जटिल नेटवर्क होता है, जिसमें छोटी सी तकनीकी खामी भी बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। एआई आधारित निगरानी प्रणाली ग्रिड के विभिन्न घटकों की लगातार निगरानी करती है और किसी भी संभावित समस्या का पहले ही संकेत दे देती है। इससे समय रहते मरम्मत और रखरखाव संभव हो जाता है, जिससे बड़े व्यवधानों को रोका जा सकता है। समिट के दौरान मंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां एआई आधारित तकनीकों के उपयोग से मेट्रो संचालन में आए सुधारों को प्रदर्शित किया गया। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने बताया कि एआई के माध्यम से मेट्रो सिस्टम की निगरानी, रखरखाव और यात्री सेवाओं को नए स्तर तक पहुंचाया गया है। अब मेट्रो ट्रेनों के विभिन्न तकनीकी घटकों जैसे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, पैंटोग्राफ, व्हील सिस्टम और सिग्नलिंग नेटवर्क की निगरानी एआई द्वारा की जा रही है।

इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह संभावित तकनीकी खामियों का पहले ही पता लगा लेती है, जिससे दुर्घटनाओं और तकनीकी विफलताओं की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेन के पहियों में असामान्य कंपन या घिसाव का संकेत मिलता है, तो एआई सिस्टम तुरंत चेतावनी जारी करता है और आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की विश्वसनीयता दोनों में सुधार हुआ है।

एआई का उपयोग केवल तकनीकी निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यात्रियों की शिकायतों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब यात्री मोबाइल ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे एआई सिस्टम तुरंत विश्लेषित कर संबंधित विभाग तक पहुंचा देता है।

दुबे के तूफान और गेंदबाजों की धार से भारत की चौथी जीत नीदरलैंड को 17 रन से हराकर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम

(जीएनएस)। अहमदाबाद। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का विजय अभियान लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद में खेले गए टूर्नामेंट के 36वें मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से हराकर अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने न केवल अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने की दिशा में भी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे शिवम दुबे, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने भी सटीक रणनीति और अनुशासित गेंदबाजी से नीदरलैंड को लक्ष्य से दूर रखा।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। यह लगातार तीसरा मैच था जब वे बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। इस शुरुआती झटके के बावजूद भारत ने तेजी से वापसी की। ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया और केवल 7 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम की रन गति को तेज कर दिया। उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और भारतीय पारी को गति प्रदान की।

इसके बाद तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए मध्यक्रम को संभाला। उन्होंने 27 गेंदों में 31 रन बनाकर टीम को स्थिरता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने विकेट बचाने के साथ-साथ रन गति को भी बनाए रखा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 28 गेंदों में 34 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और संतुलन साफ दिखाई दिया। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

हालांकि मैच का असली मोड़ तब आया जब शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और नीदरलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। दुबे ने मात्र 31 गेंदों में 66 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके और 6 लंबे छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, ताकत और तकनीक का शानदार मिश्रण देखने को मिला। दुबे ने मैदान के चारों ओर शॉट खेलते हुए विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। उनकी इस पारी ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत की ऐतिहासिक छलांग, गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 272 गीगावाट पार कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई नींव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी स्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत उत्पादन क्षमता को 272 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की ऊर्जा नीति की दूरदर्शिता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि देश तेजी से पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से हटकर पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि भारत की ऊर्जा संरचना में अब सौर और पवन ऊर्जा का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जो देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत बना रहा है। इस समय भारत की कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 141 गीगावाट तक पहुंच चुका है, जो इसे देश का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनाता है। वहीं पवन ऊर्जा भी 55 गीगावाट की क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में न केवल अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में यह विस्तार भारत को आने वाले वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में पहुंचा सकता है। भारत की इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शुरू किए गए अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल से तकनीकी सहयोग, निवेश और नीति समन्वय को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य समुद्री क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में और अधिक वृद्धि हो सके। इस अवसर पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून की उपस्थिति इस सहयोग के महत्व को दर्शाती है। यह पहल दोनों देशों के बीच 'विजन 2035' ढांचे के तहत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

अपतटीय पवन ऊर्जा को भारत की भविष्य की ऊर्जा रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ माना जा रहा है। समुद्र में स्थापित पवन टर्बाइन अधिक स्थिर और उच्च क्षमता के साथ बिजली उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। भारत के पास लंबी समुद्री तटरेखा है, जिसका उपयोग अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और तटीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी संभव होगा।

सोना वायदा में 1296 रुपये और चांदी वायदा में 8011 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा में 78 रुपये की वृद्धि

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 172191.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 19080.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 153110.27 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1771.71 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14309.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 153303 रुपये के भाव पर खूलकर, 153554 रुपये के दिन के उच्च और 152501 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151418 रुपये के पिछले बंद के सामने 1296 रुपये या 0.86 फीसदी की बढ़त के साथ 152714 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1103 रुपये या 0.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 125061 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 153 रुपये या 0.99 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15626 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 150104 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151590 रुपये और नीचे में 150104 रुपये पर पहुंचकर, 1337 रुपये या 0.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 150828 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 152624 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153385 रुपये और नीचे में 152336 रुपये पर पहुंचकर, 151517 रुपये के पिछले बंद के सामने 1173 रुपये या 0.77 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 232929 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 238564 रुपये और नीचे में 232121 रुपये पर पहुंचकर, 228783 रुपये के पिछले बंद के सामने 8011 रुपये या 3.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 236794 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 8146 रुपये या 3.52 फीसदी की बढ़त के साथ 239657 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 19080.54 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 153110.27 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 14309.70 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37500 पॉइंट के स्तर पर

8145 रुपये या 3.52 फीसदी की तेजी के संग 239667 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3191.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 14.45 रुपये या 1.26 फीसदी बढ़कर 1165.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.55 रुपये या 0.49 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 320.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 2.05 रुपये या 0.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 305.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 20 पैसे या 0.11 फीसदी की नरमी के साथ 186.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1532.41 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5658 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5720 रुपये और नीचे में 5650 रुपये पर पहुंचकर, 78 रुपये या 1.38 फीसदी बढ़कर 5720 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 79 रुपये या 1.4 फीसदी की तेजी के संग 5723 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 274.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 275.9 रुपये और नीचे में 272.7 रुपये पर पहुंचकर, 275.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.1 रुपये या 0.4 फीसदी औंधकर 274.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 1.4 रुपये या 0.51 फीसदी औंधकर 274.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 960 रुपये पर खूलकर, 1.1 रुपये या 0.11 फीसदी घटकर 959 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6062.71 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8246.99 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2716.09 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 225.82 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.08 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.09 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 813.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 705.43 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8897 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61187 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32257 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 429895 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61774 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8767 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19281 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 64525 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20515 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27141 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 37564 पॉइंट पर खूलकर, 37572 के उच्च और 37458 के नीचले स्तर को छूकर, 196 पॉइंट बढ़कर 37500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 72.4 रुपये की बढ़त के साथ 311.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 60 पैसे की नरमी के साथ 7.75 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 252 रुपये की बढ़त के साथ 2020 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 77.5 रुपये की गिरावट के साथ 314 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.96 रुपये की बढ़त के साथ 7.42 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 16 पैसे की नरमी के साथ 0.25 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 32.5 रुपये की गिरावट के साथ 251.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 पैसे के सुधार के साथ 7 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 742 रुपये की गिरावट के साथ 1958 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 297.5 रुपये की गिरावट के साथ 441 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.44 रुपये की गिरावट के साथ 3.04 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 2.9 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा पेश 2026-27 के बजट का स्वागत किया

“ यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ सहित पांच स्तंभों पर आधारित है

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

“ यह विश्वास-आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बजट है

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- 2026-27 के बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है, गत वर्ष की तुलना में बजट का आकार 10.2 फीसदी बढ़ा
- बजट के कुल खर्च का 65 फीसदी विकास-उन्मुख कार्यों के लिए आवंटित
- पर्यटन क्षेत्र को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को ‘गुजरात पर्यटन वर्ष’ घोषित कर 6500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वर्ष 2026-27 के बजट को विश्वास- आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बजट करार दिया है।

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ सहित पांच स्तंभों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट पेश किया है। गुजरात प्रधानमंत्री के हरेक संकल्प को साकार करने में उनके ही मार्गदर्शन में अविरत विकास से अग्रसर रहने वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने आज अडिग विश्वास, अविरत विकास की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा में गुजरात का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट बिना किसी नए टैक्स का बोझ डाले, राज्य की अविरत विकास यात्रा को जन कल्याण के अडिग विश्वास से आगे बढ़ाने वाला है।

उन्होंने कहा, “मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि आज पेश किया गया बजट विश्वास-आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला है।”

श्री पटेल ने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर ‘ग्यान’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 के इस बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष की तुलना में बजट के आकार में 10.2 फीसदी की वृद्धि को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने बजट आवंटन की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट के कुल खर्च का 65 फीसदी विकास-उन्मुख खर्च के लिए आवंटित किया गया है।

इतना ही नहीं, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 20 फीसदी यानी 64 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

शिक्षित, कुशल, उत्कृष्ट और भविष्य के लिए तैयार युवा शक्ति के निर्माण के लिए बजट में ‘नमो गुजरात कौशल और रोजगार मिशन’ के लिए 226 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सेवाओं के लिए 19 फीसदी और कृषि, सिंचाई, पानी और शहरी विकास के लिए 11 फीसदी आवंटन किया गया है, जो प्रधानमंत्री की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की संकल्पना को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 39 फीसदी राशि विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण सतत-अविरत और गतिशील विकास की गति को और भी तीव्र बनाएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के ग्रीन ग्रोथ के आह्वान को स्वीकार करते हुए इस वर्ष के बजट में 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रीन बजट के हिस्से के रूप में आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी साहब के विशिष्ट विजन के कारण आज गुजरात वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेर रहा है।

पर्यटन क्षेत्र को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को ‘गुजरात पर्यटन वर्ष’ के रूप में घोषित कर 6500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

श्री पटेल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है।

चार आदिवासी जिलों की 18 तहसीलों के 51,480 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) योजना का आयोजन भी किया गया है।

इसी प्रकार, आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र (जीआईडीसी) की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है।

इसके लिए, इस बजट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक परिवहन सेवाओं के साथ ही ओलंपिक रेडी अहमदाबाद के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

राज्य में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए गुजरात हाई-स्पीड कॉरिडोर में 800 करोड़ रुपए के निवेश से नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी का निर्माण होगा।

क्लाइमेट रेजिलिएंट (जलवायु लचीले) और न्यू टेक्नोलॉजी मार्गों के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीप टेक का युग है। गुजरात को एआई और डिजिटल गवर्नेंस की पहलों में आगे रखने के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है और डेटा फ्यूजन सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए संतुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और विकसित गुजरात 2047 का रास्ता और भी उज्ज्वल बनाया है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गर्व के साथ मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, “मैं एक ऐसा सर्वसमावेशी बजट देने के लिए वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिससे प्रत्येक गुजराती स्वाभिमान पर्व के साथ-साथ गुजरात के गतिमान विकास पर गर्व कर सकता है।”

“रेलवे कर्मचारियों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में सार्थक पहल - डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा द्वारा दो दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर का सफल आयोजन”

(जीएनएस)। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा (चिकित्सा विभाग) द्वारा मंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2026 को कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में दो दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर का सफल आयोजन किया गया।

इस स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय पर जाँच कर उन्हें निवारक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। शिविर के दौरान कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा स्वास्थ्य जाँच सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में कर्मचारियों को निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं— रक्तचाप (Blood Pressure – BP) जाँच

रक्त शर्करा (Blood Sugar) परीक्षण

बीएमआई एवं वजन जाँच

सामान्य चिकित्सक परामर्श

निवारक स्वास्थ्य परामर्श एवं जीवनशैली

संबंधी सुझाव

यह स्वास्थ्य शिविर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं मंडल रेलवे हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के दिशा-निर्देशानुसार, डॉ. निमी लाल, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी (ADMO), डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

चिकित्सा विभाग की समर्पित टीम द्वारा शिविर को सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जाँच, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता तथा तनाव प्रबंधन के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कर्मचारियों ने इस उपयोगी एवं जनकल्याणकारी पहल के लिए चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस प्रकार, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा द्वारा आयोजित यह स्वास्थ्य जाँच शिविर रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास सिद्ध हुआ।

सुरक्षा, सतर्कता और सेवा का संगम,अहमदाबाद मंडल आरपीएफ का सराहनीय प्रदर्शन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान यात्रियों के जीवन, सम्मान एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्क एवं प्रतिबद्ध हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जनवरी 2026 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण तथा जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मंडल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु विभिन्न अभियानों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गईः

1. रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाईः विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 2143 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 1,70,700/- का जुर्माना वसूल किया गया।
2. ऑपरेशन रेल सुरक्षाः आरपी(यूपी) अधिनियम के अंतर्गत 05 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी मामलों का पता लगाते हुए 17 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
3. ऑपरेशन यात्री सुरक्षाः यात्री सामान चोरी के 03 आरोपियों को पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर

जीआरपी को सौंपा गया।
4. सीसीटीवी के माध्यम से पहचानः सीसीटीवी निगरानी से यात्री सामान चोरी के 02 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाया गया।
5. ऑपरेशन नन्हे फरिश्तेः 12 असहाय नाबालिगों तथा 04 पुरुष/महिलाओं को सुरक्षित बचाकर उनके अभिभावकों/चाइल्डलाइन/पुलिस को सुपुर्द किया गया।
6. ऑपरेशन अमानतः 41 लावारिस/गुमशुदा सामान (मूल्य 14,55,320/-) बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया।
7. ऑपरेशन समय पालनः ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था बेहतर बनाने हेतु विशेष अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत 181 मामले दर्ज कर 166 मामलों में कार्रवाई की गई।
8. ऑपरेशन सतर्कः 31,34,995/- मूल्य की अवैध शराब के 17 मामले पकड़े गए। 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी को सौंपा गया।
9. जन जागरण अभियानः पत्थरबाजी, नशाखोरी, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। बैनर, पीए सिस्टम से घोषणाएँ, ग्राम प्रधानों/सरपंचों के साथ बैठकें तथा अहमदाबाद स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क (RDN) के माध्यम से जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए।
10. ट्रेन एस्कॉर्टिंगः प्रतिदिन औसतन 15 महत्वपूर्ण रात्रिकालीन ट्रेनों में एस्कॉर्टिंग की गई। महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्रतिदिन औसतन 03 मिश्रित (महिला एवं पुरुष स्टाफ) एस्कॉर्ट पार्टियाँ तैनात रहीं।
11. लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट मामलेः एलसी गेट क्षति के 09 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सभी मामलों का पता लगाकर 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
12. रेल मददः सुरक्षा से संबंधित 666 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन सभी का निस्तारण किया गया। औसत निस्तारण समय 0.08 मिनट रहा। प्राप्त 361 फीडबैक में से 339 यात्रियों ने उत्कृष्ट/संतोषजनक प्रतिक्रिया दी।
13. वारंट निष्पादनः रेलवे अधिनियम एवं आरपी(यूपी) अधिनियम के 74 वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।

अहमदाबाद मंडल की आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर सतर्कता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी छह जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विशेष किराए पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09183/09184 मुंबई सेंट्रल – बनारस साप्ताहिक एसी स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09183 मुंबई सेंट्रल – बनारस स्पेशल हर बुधवार को 22:30 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर शुक्रवार को 10:30 बजे बनारस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 मार्च से 25 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09184 बनारस – मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर शुक्रवार को 14:30 बजे बनारस से प्रस्थान कर रविवार को 04:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 मार्च से 27 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, अछनेरा, आगरा इदगाह, टुंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, भोगांव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जंघई एवं भदोही स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर एवं एसी 3-टियर (इकोनॉमी) के कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09189/09190 मुंबई सेंट्रल – कटिहार साप्ताहिक स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल – कटिहार स्पेशल हर शनिवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर सोमवार को 07:30 बजे कटिहार पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09190 कटिहार – मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर मंगलवार को 00:15 बजे कटिहार से प्रस्थान कर अगले दिन 18:40 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, भरूच, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया एवं नौगछिया स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09189 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09025/09026 वलसाड – दानापुर साप्ताहिक स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09025 वलसाड – दानापुर स्पेशल हर सोमवार को 08:40 बजे वलसाड से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे दानापुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी 2026 से 30 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09026 दानापुर – वलसाड स्पेशल हर मंगलवार को 14:30 बजे दानापुर से प्रस्थान कर अगले दिन 21:30 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भेस्तान, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा – गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा – गोरखपुर स्पेशल हर सोमवार को 19:00 बजे वडोदरा से प्रस्थान कर अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर – वडोदरा स्पेशल हर बुधवार को 05:00 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर अगले दिन 08:35 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फरवरी 2026 से 25 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टुंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09195/09196 वडोदरा – मऊ साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा – मऊ स्पेशल हर शनिवार को 19:00 बजे वडोदरा से प्रस्थान कर अगले दिन 20:45 बजे मऊ पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09196 मऊ – वडोदरा स्पेशल हर रविवार को 23:15 बजे मऊ से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दाहोद, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं वाराणसी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09195 का गोधरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

6. ट्रेन संख्या 09343/09344 डॉ. अंबेडकर नगर – पटना साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर – पटना स्पेशल हर गुरुवार को 18:00 बजे डॉ. अंबेडकर नगर से प्रस्थान कर अगले दिन 18:30 बजे पटना पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 फरवरी 2026 से 26 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09344 पटना – डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल हर शुक्रवार को 21:30 बजे पटना से प्रस्थान कर अगले दिन 23:55 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 फरवरी 2026 से 27 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में इंदौर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मकसी, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09183, 09189, 09025, 09111, 09195 एवं 09343 की बुकिंग 19.02.2026 सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुलेगी। ठहराव एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर देख सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा खारबाव में नई अप एवं डाउन गूड्स लाइन के कमीशनिंग हेतु दिवा वसई रोड सेक्शन में ट्रैफिक ब्लॉक

(जीएनएस)। खारबाव में नई अप एवं डाउन गूड्स लाइन के कमीशनिंग कार्य के संबंध में दिवा – वसई रोड सेक्शन में 16 से 22 फरवरी, 2026 तक ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ब्लॉक के कारण 21/22 फरवरी, 2026 को कुछ यात्री ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

21 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 61007 वसई रोड – दिवा मेमू, जो वसई रोड से 15:35 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 69166 वसई रोड – पनवेल मेमू, जो वसई रोड से 16:40 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 61006 दिवा – वसई रोड मेमू, जो दिवा से 14:33 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

4. ट्रेन संख्या 69161 पनवेल – दहानू रोड मेमू, जो पनवेल से 19:05 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

22 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 61001 बोइसर – वसई रोड मेमू, जो बोइसर से 08:35 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 61002 डोंबिवली – बोइसर मेमू, जो डोंबिवली से 05:49 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 61003 वसई रोड – दिवा मेमू, जो वसई रोड से 09:50 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

विनियमित (रेगुलेट) की जाने वाली ट्रेनः-

ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद – राजकोट एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, उसे भिवंडी रोड पर 01:30 घंटे के लिए विनियमित किया जाएगा।

री-शेड्यूल की जाने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 11087 वेरावल – पुणे एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, वेरावल से अपने निर्धारित समय 11:05 बजे के बजाय 14:35 बजे प्रस्थान करेगी।
2. ट्रेन संख्या 22944 इंदौर – दौंड एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, इंदौर से अपने निर्धारित समय 16:30 बजे के बजाय 18:30 बजे प्रस्थान करेगी।

गोरखपुर एवं मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा होली के त्योहार के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वडोदरा – गोरखपुर एवं वडोदरा – मऊ के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा – गोरखपुर स्पेशल (साप्ताहिक) [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक सोमवार वडोदरा से 19:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फ़रवरी से 23 मार्च , 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर-वडोदरा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को गोरखपुर से 05:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:35 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फ़रवरी से 25 मार्च, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, आगरा फोर्ट,टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09195/09196 वडोदरा-मऊ सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [12 फेरे]:

ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा-मऊ सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 19.00 बजे वडोदरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.45 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 फ़रवरी से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09196 मऊ- वडोदरा सुपरफास्ट स्पेशल मऊ से प्रत्येक रविवार को 23.15 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 00.45 बजे वडोदरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 फ़रवरी से 29 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दाहोद, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा फोर्ट, टूंडला,कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, और बनारस स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09195 का गोधरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09111,09195 की बुकिंग 19 फ़रवरी,2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते रेल यातायात होगा प्रभावित

(जीएनएस)। राजकोट मंडल में स्थित जामनगर-लाखाबावल सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा जिसके चलते 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, 2026 तक रेल यातायात प्रभावित होगा। प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

1) 25-02-2026 को भावनगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

2) 25-02-2026 को मुम्बई सेंट्रल से चलने वाली गाड़ी संख्या 22945 मुंबई सेंट्रल–ओखा सौराष्ट्र मेल को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

3) 24-02-2026 को शालीमार से चलने वाली गाड़ी संख्या 22906 शालीमार–ओखा

एक्सप्रेस को हापा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

4) 26-02-2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन ओखा–राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

5) 26-02-2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन ओखा–राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

6) 24-02-2026 को तिरुनेलवेली से चलने वाली गाड़ी संख्या 19577 तिरुनेलवेली–जामनगर एक्सप्रेस को हापा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-जामनगर बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

1) 26.02.2026 को पोरबंदर से चलने वाली गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया जेतलसर-भक्तिनगर से चलाया जाएगा।

रिशेड्यूल की गयी ट्रेनें:

1) 24.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को ओखा स्टेशन से 2 घंटे देरी से प्रस्थान करने के लिए रिशेड्यूल किया गया है।

मार्ग में रेगुलेट (लेट) होने वाली ट्रेनें:

1) 21, 22 और 23 फरवरी , 2026 को गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को मार्ग में 25 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

2) 23 फरवरी , 2026 को गाड़ी संख्या 12478 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–जामनगर एक्सप्रेस को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

3) 26 फरवरी, 2026 को गाड़ी संख्या 22969 ओखा–बनारस एक्सप्रेस को मार्ग में आवयश्कता अनुसार रेगुलेट किया जाएगा।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।